# राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, मध्यप्रदेश विधानसभा अधिवेशन 2006

भोपाल : मंगलवार, 14 फरवरी, 2006

**माननीय सदस्यगण,**

1. विधान सभा के आज से शुरू हो रहे सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह गर्व का विषय है कि हम मध्यप्रदेश की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस कारण इस सत्र का महत्व और बढ़ जाता है। मेरी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार और भेदभाव रहित स्वच्छ एवं संवेदनशील प्रशासन देने, प्राकृतिक संपदा का समुचित दोहन कर जन-जन के सहयोग से विकास को आंदोलन का रूप देने तथा सामाजिक व साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखते हुए प्रदेश को भारत के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है।

2. मेरी सरकार ने सड़कों के निर्माण और सुधार को उच्च प्राथमिकता देकर उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत यह कार्य बड़े पैमाने पर जारी है। विगत दो वर्षों में लोक निर्माण विभाग और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा एक हजार 858 करोड़ रुपये की लागत से 9 हजार 886 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। अगले तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं में 4 हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से करीब 16 हजार 200 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी तीन वर्षों में लगभग 25 हजार किलोमीटर सड़कों का काम करने की योजना है। इस प्रकार मेरी सरकार अगले तीन वर्षों में प्रदेश में 40 हजार किलोमीटर से भी अधिक सड़कों के निर्माण के लिए प्रयासरत् है।

3. मेरी सरकार ने प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग के अनुरूप बिजली उत्पादन की परियोजनाओं पर काम शुरू किया है जिससे वर्ष 2007-08 तक बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल हो सकेगी। सरकार द्वारा बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए एशियन विकास बैंक, नाबार्ड एवं भारत सरकार से प्राप्त लगभग रुपये 1 हजार 138 करोड़ की सहायता से कार्य किये जा रहे हैं। सरकार वर्ष 2006-07 की अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांवों के तमाम घरों को बिजली पहुंचने के काम को प्राथमिकता देगी। गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा एवं बायो फ्यूल को बढ़ावा देने का कार्य भी शुरू किया गया है।

4. मेरी सरकार प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के साथ जल संरक्षण को आंदोलन का रूप देने के लिए प्रयासरत् है। निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्र शासन, नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से संसाधन जुटाए जा रहे हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सात वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूर्णता की ओर है। मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच केन-बेतवा लिंक परियोजना के करारनामे पर दस्तखत कर प्रदेश नदी जोड़ योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विश्व बैंक की सहायता

से 1 हजार 919 करोड़ रुपये के वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के माध्मम से पांच लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बहाल हो सकेगी। जल उपभोक्ता संस्थाओं के द्वितीय चुनाव संपन्न कराकर 1 हजार 674 संथाओं को 16 लाख 74 हजार हेक्टर जल क्षेत्र का प्रबंधन सौंपा जा रहा है।

5. नर्मदा घाटी का विकास मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। इंदिरा सागर परियोजना बांध और पॉवर हाउस का निर्माण तयशुदा समय से एक साल पहले पूरा करने में हमें कामयाबी मिली है। ओंकारेश्वर, बरगी डायवर्जन, शहीद चंद्रशेखर आजाद और अपर वेदा सिंचाई परियोजनाओं का काम तेजी से जारी है। पिछले दो सालों में नर्मदा घाटी परियोजनाओं से 85 हजार 111 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है। आगामी तीन सालों में 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई तथा 1 हजार 550 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बनाने का लक्ष्य है। सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े पुनर्वास कार्य को निर्धारित लक्ष्य अनुसार किया जा रहा है। इससे प्रदेश को 826 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। नर्मदा घाटी परियोजनाओं से डूब प्रभावित आबादी को बेहतर पुनर्वास पैकेज दिया जा रहा है।

6. मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी और गर्व है कि लगातार आठ वर्षों से कृषि उत्पादकता पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ है। आज प्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। जैविक खेती में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिये मेरी सरकार कृत संकल्प है। प्रदेश के सभी जिलों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय द्वारा विगत दो वर्षों में फसलों की 22 उन्नत किस्में विकसित की गई। इस वर्ष प्रदेश के 20 जिलों में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग' का गठन किया गया है। बायोडीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रतनजोत की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

7. मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढॉचे के विकास और रोजगार की हालत में सुधार के लिए ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं पर प्रभावी अमल किया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना में विगत दो वर्षों में एक हजार 308 करोड़ रुपये के संसाधनों का उपयोग कर अधोसंरचना विकास के साढ़े तीन लाख कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दस जिलों में 450 करोड़ रुपये की योजना का क्रियान्वयन जारी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश में निर्धारित समय में अच्छी किस्म की सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसकी भारत सरकार ने भी प्रशंसा की है। विगत दो वर्षों में 942 करोड़ की लागत से 3 हजार 672 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 1 हजार 384 ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। अगले तीन वर्षों में 7 हजार ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2 फरवरी 2006 से अठारह जिलों में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग एक हजार 400 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। प्रदेश में चल रहा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन देश का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंतर्गत विगत दो वर्षों में 2 लाख हेक्टेयर में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किये गये हैं, जिससे सूखे से निपटने की क्षमता विकसित हुई है। आगामी वर्षों में

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किये जायेंगे। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत 80 हजार बी. पी. एल. परिवारों के 20 हजार स्वसहायता समूह गठित किये गये हैं और इन समूहों को आमदनी मूलक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 280 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। आगामी तीन वर्षों में इस योजना से लगभग एक लाख 50 हजार बी. पी. एल. परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। स्वरोजगारियों को बााजार उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष भोपाल में दस मेलों का आयोजन किया जा चुका है। ग्रामीण जीविका हेतु जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत दो लाख 25 हजार ग्रामीणों के 36 हजार 500 समूहों का गठन कर उन्हें 243 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में 81 लाख 28 हजार बच्चों को पका हुआ और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम का विस्तार माध्यमिक स्तर की शालाओं तक करने का लक्ष्य है। पड़त भूमि के विकास और स्वरोजगार के अवसरों के सृजन के लिए इस वर्ष 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जेट्रोफा रोपण किया गया है तथा आगामी वर्ष के लिए एक लाख 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

8. मेरी सरकार ने ग्रामोद्योग को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है। ग्रामोद्योग कलस्टरों को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पहली बार अरण्डी के पौधे पर (ईरी) रेशम उत्पादन कार्यक्रम लागू कर वर्ष 2005-06 में एक हजार दो सौ पचास एकड़ में अरण्डी पौधा रोपण किया गया है। सरकार ने ग्रामोद्योगी क्लस्टरों में कार्यरत शिल्पियों, कारीगरों एवं बुनकरों के लिए अतिरिक्त रोजगार के उद्देश्य से ग्रामोद्योग प्लस योजना शुरू की है। चंदेरी में एकीकृत हाथकरघा क्लस्टर योजना शुरू की है। विन्ध्यावैली प्रोजेक्ट के तहत बाजार सुविधा के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में विशेष परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। बाजार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश एवं देश में मेलों, उत्सवों के आयोजन के साथ, शिल्पियों/बुनकरों को विदेशों में भेजा गया है।

9. मेरी सरकार ने गौ-संवर्धन और पशुपालन के कार्य को ऊंची प्राथमिकता दी है। देशी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी नंदीशाला योजना लागू की गयी है। गौमूत्र एवं गोबर से निर्मित जैविक खाद के उत्पादन और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गौवंश वध पर पूर्ण प्रतिबंध के अधिनियम को और मजबूत बनाया जा रहा है। प्रदेश में डेयरी विकास गतिविधियों के अंतर्गत सहकारी दुग्ध समितियों के जरिये से दूध संकलन में गत वर्ष की अपेक्षा 18 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की गयी है। उपभोक्ताओं के लिए घर पहुंच सेवा लागू की जा रही है।

10. मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश में उद्योगों की स्थापना और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई औद्योगिक नीति पर अमल कर अधोसंरचना के विकास की दिशा में ठोस प्रयास किये हैं। बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी ठोस पहल की गयी है। उद्योग मित्र योजना लागू कर समस्याग्रस्त उद्योगों को फिर से पटरी पर लाया जा रहा है। बीना रिफायनरी प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हुआ है और पीथमपुर में आटो टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना को मंजूरी मिली है। सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। इस दिशा में फिक्की के सहयोग से ''डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश'' का आयोजन किया जा

रहा है। भोपाल में कनवेन्शन एंड ट्रेड सेंटर तथा ग्वालियर में हैबीटाट सेंटर की स्थापना की जा रही है। मेरी सरकार की सक्रिय पहल के फलस्वरूप भारत सरकार ने औद्यौगिक क्षेत्र, देवास को फर्मास्युटिकल्स उत्पादों के निर्यात के लिये प्रदेश का प्रथम 'टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' घोषित किया है। देश का पहला ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र इंदौर के नाम से विकसित किया जा रहा है। ग्वालियर में भी एस. ई. जेड. स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। इंदौर में क्रिस्टल, आई. टी. पार्क को केन्द्र सरकार ने आई. टी. एस. ई. जेड. घोषित किया है। रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। नई सरकार द्वारा निर्मित उद्योग मित्र वातावरण से दो वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के नये निवेश प्रस्ताव मिले हैं जिन पर कार्रवाई जारी है।

11. मेरी सरकार द्वारा वाणिज्यिक करों की वसूली व्यवस्था में किये गये सुधारों के कारण पिछले दो वर्षों में कर राजस्व में आशातीत बढ़ोत्तरी हुई है।

12. प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करना मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। इसके तहत दस नये जिलों में जिला अस्पताल खोले गये हैं। उन सभी 41 विकास खण्डों में, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की संस्था नहीं थी, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर दिये गये हैं। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये चौबीस घंटे सामान्य प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पांच सौ अस्पतालों को और सभी प्रकार की प्रसव सुविधा के लिये 170 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। गरीब महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर आने वाला सारा खर्च सरकार उठा रही है। इन प्रयासों के कारण संस्थागत प्रसव में काफी वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष नर्स के 500 अतिरिक्त पद सृजित किये जा रहे हैं। गरीबों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये सहायता हेतु लागू राज्य बीमारी सहायता निधि में एक सीमा तक मंजूरी के अधिकार जिला स्तर पर दिये गये हैं ताकि गरीब मरीजों को भोपाल के चक्कर काटने न पड़े। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिये सरकार ने सागर में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसकी स्थापना से आने वाले समय में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी।

13. मेरी सरकार ने स्कूली शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखा है। इसमें गुणात्मक सुधार तथा विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 'ऑपरेशन क्वालिटी' शुरू किया गया है। इसके लिए दूरवर्ती प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लगभग पचास हजार संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शासकीय प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 46 लाख बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश उपलब्ध कराए गए हैं। कक्षा एक से आठ तक के एक करोड़ 6 लाख बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आठवीं पास कर दूसरे गांव में नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 37 हजार से अधिक बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिलें वितरित की जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से विकासखण्ड मुख्यालयों में एक शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा तैयार

कर स्थानीय परीक्षाएं आयोजित करने का नवाचार किया जा रहा है। स्कूलों की अधोसंरचना के विकास पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष 9 हजार 862 प्राथमिक शालाओं के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्त तक प्रदेश की सभी प्राथमिक शालाओं के लिए भवन उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी स्तरों के लिए 15 हजार से अधिक अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य जारी है।

14. मेरी सरकार ने बालिका शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए 'गांव की बेटी योजना' लागू की गई है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक गांव से बाहरवीं कक्षा की प्रथम श्रेणी में अव्वल, एक बालिका को उच्च शिक्षा के लिए 500 रुपये महीना देने का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए 'स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना' प्रारम्भ की गई है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दूरस्थ अंचलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की योजना है। महाविद्यालयों में गुणवत्ता लाने के लिए प्रदेश के महाविद्यालयों का मूल्यांकन कर उनके उन्नयन का अभियान चलाया गया है। एजूसेट के माध्यम से महाविद्यालयों में सेटेलाइट टर्मिनल्स लगाकर वर्चुअल कक्षाओं के प्रसारण की व्यवस्था की गई है।

15. मेरी सरकार ने खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए नई खेल नीति लागू की है। ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व देते हुए खेल मैदानों के निर्माण और प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित की गयी है। भोपाल स्थित बड़ी झील पर 50 लाख रुपये की लागत से जलक्रीड़ा केन्द्र की स्थापना कर क्याकिंग-कैनोइंग तथा रोइंग का नियमित प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है।

अभियान' आरम्भ किया जा रहा है। जन शिकायतों के तेजी से निराकरण के लिए 'टेली समाधान' एवं समाधान ऑनलाइन' जैसे अभिनव कदम उठाये जा रहे हैं। विकासखण्ड और जिला स्तर पर नियमित रूप से 'समाधान शिविरों' का आयोजन किया जाएगा।

20. प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की काला बाजारी तथा मुनाफाखोरी रोकने का कार्य अभियान के रूप में किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से इस साल साढ़े तीन लाख टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। चने और सरसों की भी खरीदी की गई है।

21. मेरी सरकार समाज सेवी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के सहयोग से निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों तथा अनाथ कन्याओं के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जिलों में दीनदयाल अंत्योदय मिशन प्रारंभ करेगी। मिशन के अन्तर्गत अनाथ तथा निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह की योजना भी प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश में निराश्रित निधि से 21 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों का भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रों के समान उन्नयन किया गया है। अभिभावकों की भूमिका तय करने के लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड स्तर पर अभिभावक संघ स्थापित किये जा रहे हैं। मानसिक एवं सेरेबल पाल्सी से ग्रस्त निःशक्त बच्चों, दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित निःशक्त व्यक्तियों के लिये निराश्रित निधि से विशेष स्कूलों की स्थापना की जायेगी। निःशक्तजनों के लिये आई.टी.आई. और पॉलीटेकनिक संस्थाओं में उपयुक्त पाठ्यक्रमों का चयन कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रदेश के 46 लाख से अधिक गरीब परिवारों का विवेकानंद समूह

बीमा योजना के तहत बीमा कराया है। योजना के तहत प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना, मृत्यु अथवा गंभीर विकलांग होने पर 50 हजार रुपये तक की सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है।

22. मेरी सरकार ने बच्चों की सेहतमंदी और उन्हें कुपोषण से बचाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किये हैं। प्रदेश में गंभीर रूप से कुपोषित चिन्हित बच्चों को विशेष इलाज देने हेतु बाल शक्ति योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश के सभी हितग्राहियों को लाभ देने के इरादे से मेरी सरकार की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग 10 हजार नये आंगनवाड़ी केन्द्र और इक्कतीस नवीन बाल विकास परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित चौदह हजार शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चों को भी पोषण आहार दिया जायेगा। मेरी सरकार द्वारा महिलाओं पर अत्याचार तथा अन्याय को रोकने और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के इरादे से प्रदेश के 6 जिलों में 'तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना' शुरू की जा रही है।

23. मेरी सरकार ने संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। स्वाधीनता आंदोलन, क्रांतिकारियों एवं आजादी के सिपाहियों से संबंधित साहित्य का प्रकाशन तथा नाटकों और संगीत सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। महान देशभक्त एवं क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद का जन्मशती समारोह पूरे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर मनाया जायेगा। कलापंचाग का प्रकाशन शुरू किया गया है। पुरातात्विक संपदा के प्रदर्शन के लिए भव्य 16 दीर्घाओं वाला राज्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। ओरछा, धुबेला, रामनगर आदि स्मारकों के जीर्णोद्धार के साथ-साथ प्रदेश के 24 स्मारकों को संरक्षित भी किया गया है।

24. मेरी सरकार ने जंगलों की बेहतर व्यवस्था, जंगल में रहने वाले ग्रामीण भाइयों को जंगल से जोड़ने तथा जंगली जानवरों की सुरक्षा की दृष्टि से वर्ष 2005 से नई वन नीति बनाई है, जिसमें वनों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके फैलाव पर ध्यान दिया जा रहा है। इस साल मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम, 2005 में संशोधन कर वनों की सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की गयी है। मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 को अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसके अलावा जंगल की पुख्ता सुरक्षा के लिए इंटरनेट आधारित वन संरक्षण मॉनीटरिंग प्रणाली भी जल्दी लागू की जायेगी। प्रदेश के 539 वन ग्रामों के विकास की योजना शुरू की गई है शेष वन ग्रामों के लिए भी योजना तैयार की जायेगी। जंगल के विकास तथा जंगल में रहने वाले वनवासियों के विकास के लिये 17 नये वन विकास अभिकरण मंजूर किये गये हैं। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए 'इको पर्यटन बोर्ड' का गठन किया गया है, जो इन इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास का मुख्य काम करेगा। मेरी सरकार ने तेंदूपत्ता के संग्राहकों को अधिक लाभ देने की दृष्टि से तेंदूपत्ता व्यापार की शुद्ध आमदनी से दिये जाने वाले प्रोत्साहन पारिश्रमिक को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। संयुक्त वन प्रबंध समितियों को इमारती लकड़ी और बांस के विदोहन से मिलने वाली आय में से लगभग 29 करोड़ रुपये लाभांश के रूप में देने का फैसला लिया गया है।

25. मेरी सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये कदम उठा रही है। प्रत्येक वर्ष दस जिलों में तारामण्डल स्थापित किये जा रहे हैं। अभी तक 20 जिलों में तारामण्डल स्थापित करने की कार्यवाही की जा चुकी है। सभी जिलों के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का डिजीटल डाटा बेस तैयार किया जा रहा है।

26. मेरी सरकार प्रदेश के लिए नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति बना रही है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इन्दौर में साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क बनाया गया है। भोपाल एवं ग्वालियर में भी पार्क निर्माण किया जाएगा। डिजीटल सूचना के संचार के लिए राज्य में स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को सेवायें एवं जानकारी सुगमता से हासिल होंगी।

27. मेरी सरकार ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सूचना आयोग का गठन तथा अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। आयोग ने माह अक्टूबर से कार्य शुरू कर दिया है।

28. मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए जैव विविधता नियम अधिसूचित कर मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया है। इसी प्रकार जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये जैव प्रौद्योगिकी परिषद का भी गठन किया है। भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ लाईफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

29. मेरी सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अगले पांच वर्षों के लिए प्राप्त होने वाली 361 करोड़ रुपये की राशि से नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट) डाटाबेस मैनेजमेंट तथा जलप्रदाय योजनाओं की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष से चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान का युक्तियुक्तकरण किये जाने से नगर पंचायतें लाभान्वित हुई हैं। भोपाल, इन्दौर, जबलपुर और उज्जैन शहरों के समग्र विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत योजना बनाई गई है। अधोसंरचना विकास के लिए अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउंस शुरू की गई है। मेरी सरकार नें चयनित अयोध्या बस्तियों के समेकित विकास के लिए 18 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। अब तक नगरीय निकायों की 357 अयोध्या बस्तियों का चयन कर उनमें विकास कार्य प्रारंभ किये गये हैं।

30. मेरी सरकार ने इस वर्ष 10 हजार से अधिक ऐसी बसाहटों में जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है या अपर्याप्त है, वहां पेयजल व्यवस्था की है। इसी प्रकार शासकीय भवन वाली 5 हजार से ज्यादा ग्रामीण शालाओं में पयेजल की व्यवस्था की है। समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 3 लाख 50 हजार से अधिक व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा पाठशालाओं में शौचालय बनाये जा रहे हैं। पेयजल में फ्लोराइड एवं खारे पानी की समस्या के निदान के उपाय किए जा रहे हैं।

31. मेरी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रभावी प्रयास कर रही है। प्रदेश के 17 प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाले मार्गों का प्राथमिकता पर सुधार और रख-रखाव किया जा रहा है। विभिन्न जलाशयों एवं नदियों में जलक्रीड़ाओं तथा रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुरहानपुर और इन्दौर को नये स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार ने पर्यटकों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 38 आवासीय इकाईयों का उन्नयन तथा 12 इकाईयों का विस्तार किया है।

32. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिये न्यायालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हुए न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की गई है। इस दिशा में जिला श्योपुर, बड़वानी और हरदा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के

न्यायालय स्थापित किये गये हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, पारवारिक न्यायालयों के न्यायाधीश, लिपिकीय श्रेणी में पदों का सृजन किया गया है। मेरी सरकार ने न्यायालयों में काम का बोझ कम करने के उद्देश्य से करीब सत्तर हजार मामूली प्रकृति के लंबित प्रकरण वापस लिये हैं। सरकार ने न्यायाधीशों के आवास एवं न्यायालय भवन का निर्माण भी प्राथमिकता से किया है।

33. मेरी सरकार ने छोटे और मझोले 17 नगरों की परियोजनाओं के लिये कुल 686 लाख 70 हजार रुपये का अनुदान स्थानीय संस्थाओं को उपलब्ध कराया है। छोटे तथा मझोले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना लागू की जायेगी। मेरी सरकार ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के सात नगरों उज्जैन, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर और चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित कर वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के काम शुरु किए हैं।

34. मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को प्राथमिकता दी है। इस वर्ग की छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये करीब एक लाख 50 हजार कन्याओं को कन्या साक्षरता प्रोत्साहन का लाभ दिया गया। इसके साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति तथा सिविल सेवा परीक्षा के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष विभाग द्वारा संचालित प्री-मेट्रिक छात्रावासों में कम्प्यूटर प्रदान किये जायेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा में गुणवत्ता के प्रयास से अच्छे परिणाम आना शुरू हुए हैं। अति विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की व्यवस्था की जायेगी। इस वर्ष अड़तीस प्री-मेट्रिक छात्रावासों को उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। भवनविहीन संस्थाओं को भवन उपलब्ध कराना हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है। जिन विकास खण्डों पर छात्रावास व्यवस्था नहीं है उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास प्रारंभ करने का प्रयास किया जायेगा। सरकार द्वारा आदिवासियों की संस्कृति, कला और बोलियों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

मेरी सरकार ने इन वर्गों के चहुंमुखी विकास पर समुचित ध्यान दिया है। डेरी विकास, वनग्रामों का विकास, वन ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ-साथ मोहल्लों, मजरों, टोलों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। छात्र-छात्राओं के लिये स्वरोजगार देने वाला कम्प्यूटर प्रशिक्षण लागू किया गया है। मेरी सरकार विमुक्त जाति की कन्याओं के लिये और अधिक आश्रम सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पुरजोर प्रयास करेगी।

35. मेरी सरकार ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के 538 हितग्राहियों को इस वर्ष 2 करोड़ रुपये तथा पिछड़ा वर्ग के 777 हितग्राहियों को 3 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने की कार्यवाही की है। पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये 8 संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, रीवा, उज्जैन तथा सागर में सौ सीटर छात्रावास भवन के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर पिछड़ा वर्ग की कन्याओं के लिये छात्रावास भवन निर्माण की कार्यवाही जारी है। मेरी सरकार ने वक्फ की सम्पत्ति की सुरक्षा के कदम उठाए हैं।

36. मेरी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण की दिशा में दूरगामी कदम उठाये हैं। प्रदेश के 17 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चलाई जा रही है।

37. मेरी सरकार ने सहकारी बैंकों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिये अनेक उपायों पर काम शुरू किया है। प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन की

अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पहल की गई है। फलस्वरूप प्रदेश में कृषि सहकारी साख संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिल सकेगी। सहकारिता आंदोलन में राजनैतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने एवं प्रशासनिक स्वच्छता की दृष्टि से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। प्रदेश के तेरह जिलों में नई एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं को चलाने का निर्णय लिया गया है।

38. मेरी सरकार ने 8 जिलों की 22 तहसीलों को पूरी तरह तथा 2 तहसीलों में चुने हुए ग्रामों के समूह को सूखा प्रभावित घोषित किया है। सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांच किलोमीटर दायरे में रोजगारमूलक कार्य शुरू करने की व्यवस्था की है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को देय राहत राशि में पहले से दोगुनी वृद्धि की है।

39. मेरी सरकार ने प्रदेश में परिवहन सेवाओं को पारदर्शी एवं सुलभ करने की दृष्टि से समस्त जिला कार्यालयों को 'कम्प्यूटरीकृत' किया है। सभी स्थाई वाहन चालन लायसेंस और वाहनों का पंजीयन प्रमाण-पत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी किया जा रहा है। प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों का निजीकरण किया गया है। अब तक 681 राष्ट्रीयकृत मार्गों में से 508 मार्गों का निजीकरण किया गया है। यात्रियों को अतिरिक्त सेवायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम ने एक हजार 200 से अधिक निजी बसों को अनुबंधित किया है। विभागीय उड़नदस्तों को समाप्त किया गया है तथा जिला कार्यालयों में एकल खिड़की प्रणाली स्थापित की गई है। इससे इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2005 तक 2 लाख 39 हजार आवेदनों का निपटारा हुआ है। महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सभी विभागों के लिये 'एकीकृत जांच चौकियों' की स्थापना की जा रही है। सरकार ने दिसम्बर 2005 तक 388 करोड़ 54 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम के परिसमापन का निर्णय लेकर अब तक चार हजार कर्मचारियों को 135 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुदान व बकाया का भुगतान किया है।

40. मेरी सरकार भोपाल और इन्दौर विमानतलों के विस्तार के लिये प्रयासरत है।

41. मेरी सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना है। पुलिस को जनोन्मुखी एवं संवेदनशील बनाने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। पुलिस के आधुनिकीकरण की केन्द्र प्रवर्तित योजना में 98 करोड़ 95 लाख रुपये की योजना मंजूर हुई है। इससे वाहन, उपकरण, दूरसंचार उपकरण एवं अन्य आधुनिकीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत थाना भवनों, महिला प्रसाधन कक्षों के निर्माण पर लगभग 13 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा मृत सैनिकों के आश्रितों और विकलांग सैनिकों को एक करोड़ 63 लाख रुपये की मदद दी गयी है। एक अभियान चलाकर 2 लाख बच्चों को यातायात का प्रशिक्षण दिया गया है।

42. माननीय सदस्यगण मेरे अभिभाषण को आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिये मैं आभारी हूं।

जयहिन्द।